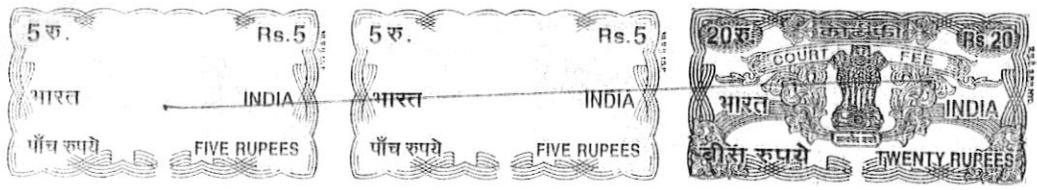


146

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा(म0प्र0)



20/11

Rs 30/-

गुलाब सिंह तनय पर्वत सिंह निवासी ग्राम मड़वार, तहसील रामनगर
जिला- सतना म0प्र0निगरानीकर्ता

अधि० श्री रघुवंश प्रताप
सिंह द्वारा पेश/30-6-17

बनाम

1. रामखेलावन साकेत पिता संग्राम साकेत निवासी ग्राम मड़वार, तहसील
अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

2. म0प्र0 शासनगैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
बृत्त बड़वार, तहसील रामनगर, जिला सतना
म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्रमांक 8ए5/13-14
आदेश दिनांक 23.7.014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता

मान्यवर,

निगरानी ज्ञापन के आधार निम्न है:-

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि भूमि आराजी नम्बर
18/375/1 रकवा 0.300 हे० स्थित मौजामड़वार, प० ह० हरदुवा, रा० नि० मं० बड़वार,
तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0 स्थित भूमि के संयुक्त रूप से पूर्व
में रामखेलावन, मुन्ना, रामसुजान, पिता संग्राम दर्ज राजस्व अभिलेख थे।
आपसी विभाजन में 18/375 /1 क रकवा 0.150 हे० पूर्व तरफ एवं
भूमि आराजी नम्बर 18/375/1ख रकवा 0.150 हे० रामसुजान को
पश्चिम तरफ मिली, उक्त मूल नम्बर 18/375/1 के बीचों बीच में
गोरसारी बरही सड़क शासन द्वारा निकाली गयी है, जिस सड़क में
रामसुजान के हिस्से में से 0.050 हे० भूमि सड़क में अधिग्रहीत कर ली
गयी, शेष 0.100 हे० भूमि सड़क के पश्चिम तरफ कब्जे में बची रही,
जिस बची हुयी भूमि को निगरानीकर्ता दिनांक 13.6.014 को बिक्रय कर

कलकत्ता
राजस्व मण्डल म० प्र०
(सर्किट कोर्ट) रीवा

Handwritten signature

Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III/निग0/सतना/17/2024

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-8-2017	<p>आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार वृत्त बडवार तहसील रामनगर जिला सतना के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30-7-2014 की सत्यापित प्रति एवं अन्य सत्यापित दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित सूचना पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को विधिवत सूचना जारी की गई है जिसपर उसके हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। आवेदक द्वारा तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30-7-2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में 33 माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> (एस0एस0 अली) सदस्य</p>	